# *निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2021-22 में वृद्धि और 2022-23 के लिए दृष्टिकोण**

*भारत में निजी निवेश गतिविधि के लिए निकट अवधि के दृष्टिकोण का अनुमान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के परियोजना निवेश प्रस्तावों से लगाया जाता है। कोविड-19 महामारी के कम होने के बाद व्यावसायिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने और मांग की स्थिति में सुधार के साथ, 2021-22 के दौरान नई परियोजनाओं की घोषणा में काफी वृद्धि हुई, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की। 2021-22 के दौरान परिकल्पित कुल कैपेक्स निवेश में से एक तिहाई से अधिक 2022-23 में खर्च किए जाने की उम्मीद है।*

**परिचय**

निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश वातावरण को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, विकास की संभावनाओं का आकलन करने के लिए निजी निवेश दृष्टिकोण का आकलन महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के वार्षिक खातों के प्रकाशन में देरी को देखते हुए, तुलन पत्र आधारित निवेश दर अल्पकालिक निवेश दृष्टिकोण का आकलन करने में उपयोगी नहीं हो सकती है। एक विकल्प के रूप में, परिकल्पित कॉर्पोरेट निवेश योजनाओं और निवेश भावना के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण-आधारित विधियों का लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। इस तरह के सर्वेक्षणों के परिणाम वर्तमान निवेश माहौल और निवेश के इरादे दोनों के आकलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिनके लघु से मध्यम अवधि में कार्यान्वित होने की संभावना है।

भारत में भी, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही निजी निवेश के आकलन और पूर्वानुमान/नव-कास्टिंग के लिए इस तरह के सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की कैपेक्स योजनाओं का उपयोग रंगराजन (1970) [1] द्वारा कैपेक्स के समय चरणबद्ध तरीके से अपनाई गई पद्धति के आधार पर निवेश पर एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए किया गया है। इस तरह के लेख शुरू में आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक और बाद में 1989 से आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किए गए थे।

यह लेख पांच खंडों में सृजित किया गया है। खंड II कार्यप्रणाली और इसकी सीमाओं को निर्धारित करता है। समीक्षा की अवधि के दौरान स्वीकृत या अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएँ, उनका वित्तपोषण, और क्षेत्रों और उद्योगों के संदर्भ में वितरण संबंधी पहलुओं को खंड III में प्रस्तुत किया गया है। खंड IV स्वीकृत/अनुबंधित ऋण/वित्तपोषण के चरणबद्ध प्रोफाइल से संबंधित है और कॉर्पोरेट निवेश की वृद्धि का अनुमान लगाता है। खंड V अध्ययन का समापन करता है।

**II. कार्यप्रणाली और सीमाएं**

यह लेख निजी कॉर्पोरेट की निवेश गतिविधि के निकट अवधि के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए रंगराजन (1970) का अनुसरण करता है। इस उद्देश्य के लिए, निवेश के इरादे पर डेटा तीन अलग-अलग स्रोतों के माध्यम से एकत्र किया गया था, अर्थात, i) बैंक और वित्तीय संस्थाएं (एफआई) [2] जो निजी कंपनियों को परियोजना वित्त के कारोबार में शामिल हैं, (ii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), रुपये में मूल्यवर्गित बांड (आरडीबी) जारी करने सहित बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के माध्यम से पूंजीगत व्यय उद्देश्य के लिए उठाए गए वित्त, और (iii) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और एक वर्ष के दौरान राइट्स इश्यू।

---

* यह लेख सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के कॉर्पोरेट अध्ययन प्रभाग में राजेंद्र एन चौहान और राजेश बी कावेड़िया द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। "निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2020-21 में वृद्धि और 2021-22 के लिए आउटलुक" श्रृंखला में पिछला लेख भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के सितंबर 2021 के अंक में प्रकाशित हुआ था।

[1] यह पद्धति 19 दिसंबर, 1970 को डॉ. सी. रंगराजन द्वारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू), खंड संख्या 5, अंक संख्या 51, पृष्ठ 2049-2051 में लिखे गए लेख "कॉर्पोरेट क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का पूर्वानुमान" में प्रकाशित हुई थी।

[2] में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्रमुख निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं जो परियोजना वित्तपोषण में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जैसे कि भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आईएफसीआई), जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आरईसी) और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम)।

पूंजी निवेश की दोहरी गणना और परिणामस्वरूप अतिवृद्धि से बचने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि प्रत्येक पूंजीगत व्यय परियोजना केवल एक बार निर्धारित जानकारी में प्रवेश करती है, भले ही इसे आरबीआई के आंतरिक डेटाबेस के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके कई स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया हो। इस अध्ययन में केवल उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जो ऊपर उल्लिखित किसी भी स्रोत के माध्यम से वित्तपोषित हैं, जिनकी परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है और निजी स्वामित्व 51 प्रतिशत से ऊपर है। केंद्र और राज्य सरकारों, ट्रस्टों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है।

अनुमान इस धारणा के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं कि कंपनियां अपनी प्रत्याशित पूंजीगत व्यय योजनाओं का पालन करती हैं। हालांकि, ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) में उपलब्ध कॉर्पोरेट निश्चित निवेश के पूर्व-पश्च अनुमानों से अलग हो सकते हैं। यह इस संभावना के मद्देनजर है कि कुछ प्रत्याशित लक्ष्य उनकी राशि और निवेश के समय के संदर्भ में वास्तविक निवेश में फलीभूत नहीं हो सकते हैं और कुछ परियोजनाएं स्व-वित्तपोषित हो सकती हैं।

## III. स्वीकृत/अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएं

नई परियोजना घोषणाओं की संख्या के संदर्भ में निवेश का माहौल 2019-20 के दौरान कमजोर रहा और 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण और बिगड़ गया। इसके बाद, व्यावसायिक गतिविधियों की बहाली और मांग की भावना में सुधार के साथ, नई कैपेक्स परियोजना घोषणाओं ने पुनरुद्धार के कुछ संकेत दिखाए। 2021-22 के दौरान, 28 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जो परियोजना वित्त में सक्रिय रूप से शामिल थे, ने 403 परियोजनाओं की सूचना दी, जो 2020-21 के दौरान रिपोर्ट की गई 220 परियोजनाओं की रिपोर्ट के साथ-साथ 2019-20 के दौरान रिपोर्ट की गई 320 परियोजनाओं से काफी अधिक थी, मुख्य रूप से छोटी टिकट परियोजनाओं में वृद्धि के कारण . हालांकि, कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन और संबंधित प्रतिबंधों के कारण 2020-21 में ₹75,558 करोड़ के रिकॉर्ड निचले स्तर की तुलना में ₹1,43,314 करोड़ की कुल परियोजना लागत लगभग दोगुनी हो गई थी, लेकिन यह पूर्व-कोविड स्तरों से कम रही (संलग्नक: सारणी ए1)।

कुल 361 कंपनियों ने, जिन्होंने पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कोई वित्तपोषण नहीं लिया, ने ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के माध्यम से 47,824 करोड़ रुपये की राशि जुटाई और 27 अन्य कंपनियों ने आईपीओ मार्ग के तहत घरेलू इक्विटी निर्गम के माध्यम से अपनी पूंजीगत खर्च जरूरतों के लिए 3,410 करोड़ रुपये जुटाए। कुल मिलाकर, 2021-22 के दौरान 791 परियोजनाओं की निवेश योजना बनाई गई, जो 2020-21 में 576 परियोजनाओं के मुकाबले ₹1,16,603 करोड़ के निवेश के इरादे से ₹1,94,548 करोड़ थी, जो कि 2016-17 के बाद से देखे गए स्तरों से तुलनात्मक रूप से कम रही। (अनुलग्नक: सारणी ए1-ए 4)।

### (i) आकार के अनुसार

2020-21 और 2021-22 के दौरान कुल परियोजना लागत में मेगा परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी (₹5,000 करोड़ और अधिक) में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। बड़ी परियोजनाओं (परियोजना लागत: ₹1,000 करोड़ - ₹5,000 करोड़) ने 2021-22 के दौरान स्वीकृत परियोजना लागत में काफी अधिक हिस्सेदारी (47 प्रतिशत) का योगदान दिया। हालांकि 2021-22 के दौरान बड़ी परियोजनाओं की संख्या पिछले वर्ष के दौरान 24 परियोजनाओं से बढ़कर 36 हो गई, लेकिन परियोजनाओं की कुल लागत में उनकी हिस्सेदारी 2021-22 के दौरान कम हो गई (संलग्नक: सारणी ए5)।

### (ii) उद्देश्य-वार

2021-22 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई कुल परियोजना लागत में ग्रीनफील्ड (नई) परियोजनाओं में निवेश का प्रमुख हिस्सा (89 प्रतिशत) रहा, जो अतीत में देखे गए रुझान से तुलनीय है। परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान काफी वृद्धि हुई है, जो 2019-20 के दौरान घोषित ग्रीन फील्ड परियोजनाओं से भी अधिक है। कुल परियोजना लागत का 11 प्रतिशत मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए निर्देशित किया गया था (अनुलग्नक: सारणी ए6)।

### (iii) उद्योग-वार

2020-21 से 2021-22 में कुल परियोजना लागत में वृद्धि हुई है, जिसमें कई उद्योगों ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। उदाहरण

**चार्ट 1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख उद्योगों का हिस्सा**

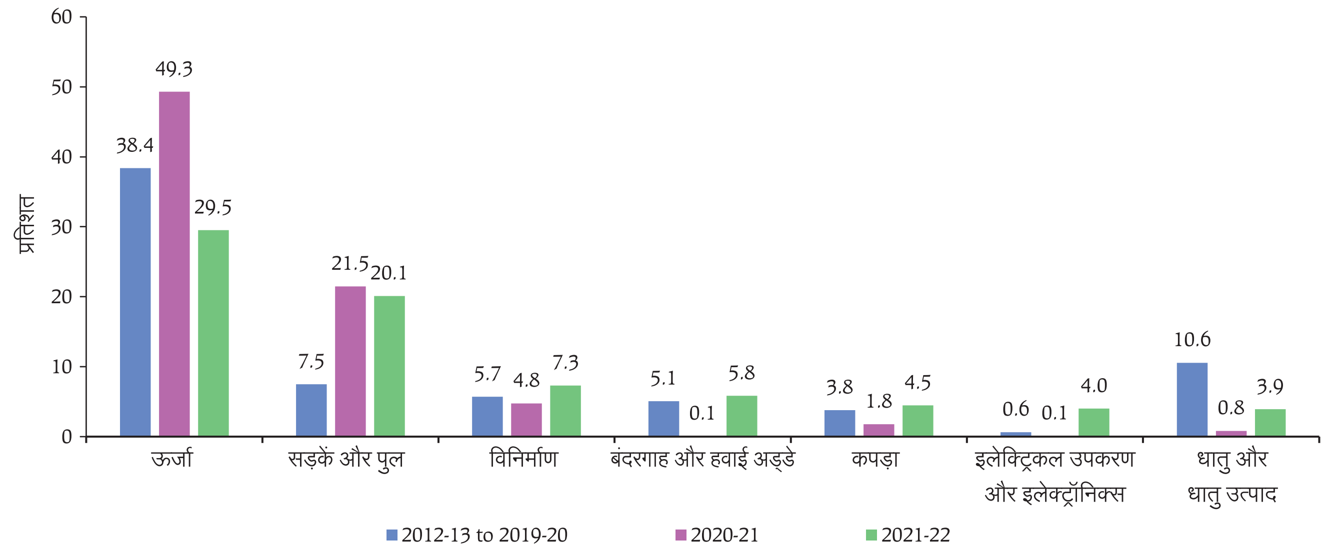


**स्रोत:** बैंकों/वित्तीय संस्थानों और लेखक की गणना से परियोजना वित्त पर डेटा एकत्र किया गया।

के लिए, इस अवधि के दौरान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कुल लागत 56,103 करोड़ रुपये से बढ़कर 81,221 करोड़ रुपये हो गई। गैर-बुनियादी ढांचा क्षेत्र में, निर्माण, कपड़ा, विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स और धातु और धातु उत्पादों जैसे उद्योगों ने 2021-22 में परिकल्पित परियोजनाओं की कुल लागत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की (अनुबंध: सारणी ए 7)।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र, जिसमें (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (iv) भंडारण और जल प्रबंधन, (v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क, और (vi) सड़कें और पुल शामिल हैं, 2021-22 के दौरान कुल परियोजना लागत के आधे से अधिक के लिए प्रमुख क्षेत्र बने रहे। हालांकि, इसी अवधि के दौरान परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद कुल परियोजना लागत में इसकी हिस्सेदारी 2020-21 में 74.3 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 56.7 प्रतिशत हो गई है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की हिस्सेदारी में गिरावट मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी से प्रेरित थी, भले ही इसने बैंकों / वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। इसके अलावा, 2012-13 से 2019-20 की तुलना में हाल के वर्षों में 'सड़क और पुलों' में निवेश की हिस्सेदारी में काफी सुधार हुआ है। इसके विपरीत, 'धातु और धातु उत्पादों' में निवेश का हिस्सा 2012-13 से 2019-20 के दौरान अपने हिस्से की तुलना में काफी कम रहा, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में इसमें सुधार हुआ (चार्ट 1)।

बिजली क्षेत्र के भीतर, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में परियोजना घोषणाएं 2021-22 के दौरान प्रमुख रहीं, जो अक्षय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत पहलों को दर्शाती हैं (बॉक्स 1)।

**बॉक्स 1: अक्षय ऊर्जा पर जोर**

पर्यावरण और समग्र अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, दुनिया भर के अधिकांश देश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से गैर-पारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में स्थानांतरित करने के अपने प्रयास कर रहे हैं। कई विकसित और विकासशील देशों ने समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पेरिस में पार्टियों के वार्षिक सम्मेलन (सीओपी)-21 के दौरान, भारत ने भी प्रतिबद्धता जताई कि वह 2030

*(Contd.)*

तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत हासिल कर लेगा । इसके अलावा, ग्लासगो, यूके में सीओपी-26 में, माननीय भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने पांच महत्वाकांक्षाओं की घोषणा की जिसमें शामिल हैं (i) भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 जीडबल्यू तक पहुंचाना और, (ii) भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत पूरा करेगा।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल की। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति के अंतर्गत नवीकरणीय पुनर्खरीद दायित्व (आरपीओ) का प्रावधान, सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास, उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण और सौर पैनलों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें, हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के माध्यम से विद्युत पारेषण नेटवर्क का विकास, बैंकों द्वारा प्रदान किए गए आवास ऋण के भाग के रूप में सौर रूफ टॉप को अनिवार्य बनाना शामिल है। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों में छूट, नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास का समर्थन करना, स्वचालित मार्ग [3] के माध्यम से इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, भारत ने नवंबर 2021 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल किया है - प्रतिबद्ध समय सीमा से नौ साल पहले अपने एनडीसी को हासिल करने वाला पहला देश। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, मार्च 2022 तक, अक्षय ऊर्जा (परमाणु आधारित सहित) की स्थापित क्षमता लगभग 163 गीगावॉट है, जो कुल स्थापित क्षमता का 41 प्रतिशत है।

**अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति**

2014 के बाद से कुल स्थापित क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, जो मार्च 2014 में 75.5 गीगावॉट से बढ़कर मार्च 2022 तक 156.6 गीगावॉट हो गई। महामारी के कारण आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद, जो रूस-यूक्रेन युद्ध और पवन और सौर ऊर्जा घटकों की कीमतों में वृद्धि से और बढ़ गया था, भारत 2021-22 के दौरान लगभग 15 गीगावॉट क्षमता जोड़ने में सक्षम था, जिससे मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 के अंत तक कुल स्थापित क्षमता में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आरईएन 214 की 'रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट' के अनुसार, दिसंबर 2021 के अंत में संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में, भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर रहा। साथ ही, नई क्षमता वृद्धि के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा।

कुल स्थापित क्षमता में स्थापित सौर क्षमता का हिस्सा मार्च 2014 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 में 28.5 प्रतिशत और मार्च 2022 में 34.5 प्रतिशत हो गया। औसतन, 2014-2022 के दौरान अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में बड़े जल विद्युत संयंत्रों और पवन ऊर्जा का हिस्सा लगभग 41 प्रतिशत और 29 प्रतिशत था (चार्ट 2)।

राज्यों में, अप्रैल 2022 तक, राजस्थान ने कुल स्थापित क्षमता में 15.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। कुल स्थापित क्षमता में, शीर्ष 5 राज्यों, अर्थात् राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की कुल हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत है।

**चार्ट 2: अक्षय ऊर्जा : स्थापित क्षमता (मार्च -अंत)**

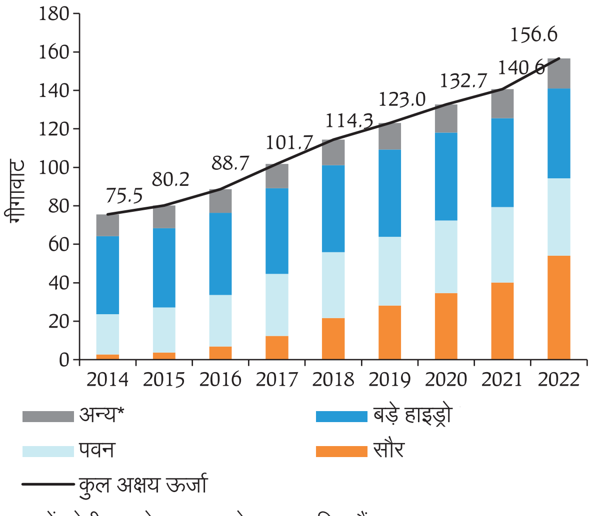


*अन्य में छोटी हाइड्रो पावर, बायो पावर शामिल हैं
**स्रोत:** केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण

*(Contd.)*

[3] https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177515

[4] आरईएन 21 वैश्विक अक्षय ऊर्जा समुदाय है, जिसे 2004 में अक्षय ऊर्जा पर बॉन 2004 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणामस्वरूप बनाया गया था। इसका अधिदेश वास्तविक समय के आधार पर स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा डेटा के एक विशाल निकाय को एकत्र करना, समेकित करना और संश्लेषित करना है।

**चार्ट 3: अपरंपरागत ऊर्जा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह**

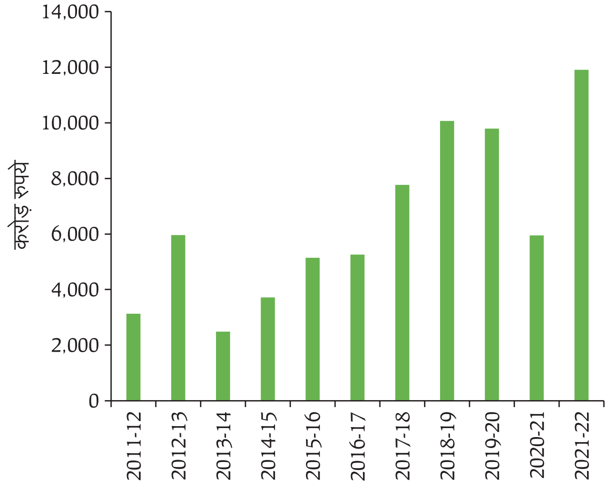


**स्रोत:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार

**अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश**

अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के दौरान, गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को 75,000 करोड़ रुपये का एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 2 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है। 2021-22 में, इस क्षेत्र ने 11,905 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च एफडीआई इक्विटी प्रवाह पर कब्जा कर लिया (चार्ट 3)।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, अधिकांश ऊर्जा मांग अभी भी जीवाश्म ईंधन स्रोतों के माध्यम से पूरी की जाती है। इस क्षेत्र में निवेश के इरादों को मूर्त रूप देने, जैसा कि शीर्ष कंपनियों ने अपनी नवीनतम वार्षिक निवेशक बैठक में घोषणा की थी, सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के साथ संभवतः अक्षय क्षेत्र में पर्याप्त निवेश में बदल सकता है।

**(iv) राज्यवार**

राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 के दौरान, आधे से अधिक (56.4 प्रतिशत) परियोजनाएं पांच राज्यों, अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शुरू की गईं। इन पांच राज्यों की हिस्सेदारी 2012-13 से 2019-20 के दौरान 40.7 प्रतिशत की औसत हिस्सेदारी से बढ़कर पिछले दो वर्षों के दौरान 50.0 प्रतिशत से अधिक हो गई। (चार्ट 4 और अनुलग्नक: सारणी ए 8)।

2021-22 में, राजस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में सबसे अधिक हिस्सा

**चार्ट 4: बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में मुख्य राज्यों का हिस्सा**

विविध राज्य: एक राज्य से अधिक राज्यों में फैली हुई परियोजनाएं

**स्रोत:** परियोजना वित्त से संबन्धित आंकड़े बैंकों /वित्तीय संस्थाओं एवं लेखक की स्वयं की गणना के आधार पर एकत्र किए गए हैं।

लिया, जो लगातार दो वर्षों तक शीर्ष स्थान पर बना रहा। जबकि 2021-22 के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात की हिस्सेदारी में गिरावट आई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक ने परियोजनाओं की कुल लागत में अपने हिस्से में सुधार किया (चार्ट 4 और अनुबंध: सारणी ए 8)।

### 4. निवेश लक्ष्यों की चरणबद्ध प्रोफाइल

विभिन्न वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से परिकल्पित पूंजीगत व्यय के चरणबद्ध प्रोफाइल की जानकारी पूंजीगत व्यय के अल्पकालिक (एक वर्ष आगे) पूर्वानुमान उत्पन्न करने में मदद करती है। 2021-22 में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से चरणबद्ध तरीके से संकेत मिलता है कि कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग 41.8 प्रतिशत (59,897 करोड़ रुपये) उसी वर्ष खर्च होने की उम्मीद थी, जबकि 30.9 प्रतिशत (44,282 करोड़ रुपये) 2022-23 में और अन्य 17.6 प्रतिशत (25,267 करोड़ रुपये) खर्च होने की संभावना है। 2021-22 में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में से 9.7 प्रतिशत 2021-22 से पहले ही खर्च किया जा चुका था। नियोजित व्यय से, बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2021-22 में परिकल्पित पूंजीगत व्यय में 3.8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो 2020-21 के दौरान 1,33,498 करोड़ रुपये से घटकर 2021-22 के दौरान 1,28,366 करोड़ रुपये हो गया (अनुबंध सारणी ए 1)।

2021-22 में ईसीबी के जरिये जुटाए गए संसाधनों से होने वाला पूंजीगत व्यय एक साल पहले के स्तर से 73.4 प्रतिशत बढ़कर 64,178 करोड़ रुपये हो गया। पूंजी बाजार (इक्विटी मार्ग) ने 2021-22 में 1,178 करोड़ रुपये के परिकल्पित पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण को सक्षम किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है (अनुबंध: सारणी ए 2, ए 3)। कुल मिलाकर, 2021-22 में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा 1,93,722 करोड़ रुपये का कुल पूंजीगत व्यय निवेश किए जाने की उम्मीद थी, जो पिछले वर्ष के नियोजित चरणों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस वृद्धि को ईसीबी मार्ग के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है (अनुबंध: सारणी ए 4)।

संदर्भ वर्ष से पहले पिछले वर्षों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत पाइपलाइन परियोजनाओं [5] के आधार पर परिकल्पित पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध प्रोफाइल 2021-22 में 68,469 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 71,012 करोड़ रुपये हो गया; लेकिन वित्तपोषण के सभी चैनलों के आधार पर, यह 2021-22 में 1,07,535 करोड़ रुपये की तुलना में 2022-23 में 97,644 करोड़ रुपये पर कम रहा (अनुबंध: तालिका ए 1 और ए 4)।

## V. निष्कर्ष

यह लेख निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा उनके परियोजना प्रस्तावों की चरणबद्ध योजनाओं (पूर्व-पूर्व) के आधार पर निवेश इरादों पर डेटा का उपयोग करता है ताकि कुल निवेश इरादों पर पहुंचा जा सके और निकट अवधि में निवेश गतिविधि के दृष्टिकोण का आकलन किया जा सके। महामारी की अवधि में वापस आने के बाद, 2021-22 के दौरान नई निवेश परियोजनाओं की घोषणाओं में काफी वृद्धि हुई, परियोजना की कुल लागत में 2020-21 की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे बनी हुई है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने 'बिजली' और 'सड़क और पुल' क्षेत्रों के नेतृत्व में अधिकतम पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को आकर्षित करना जारी रखा। सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों को दर्शाते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश पिछले कुछ वर्षों में आकर्षण प्राप्त कर रहा है। इससे सीओपी-26 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

आने वाले समय में निजी कंपनियों की बैलेंस शीट में सुधार, क्षमता उपयोग के बढ़ते स्तर, मजबूत मांग धारणा, उच्च पूंजीगत खर्च और सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत पहलों से पूंजीगत व्यय चक्र में नई जान आने की उम्मीद है।

[5] पाइपलाइन परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो कार्यान्वयन के लिए पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। एक पाइपलाइन परियोजना से कैपेक्स किसी दिए गए वर्ष के लिए परिकल्पित राशि है, जो उस दिए गए वर्ष से पहले स्वीकृत हो गई थी।

## अनुबंध

### सारणी ए1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

| स्वीकृति का वर्ष ↓ | परियोजनाओं की संख्या | स्वीकृति के वर्ष में परियोजना लागत (₹ करोड़ में) | रद्दीकरण के कारण परियोजना लागत - (₹ करोड़ में) | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2022-23 से आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2012-13 तक | | | | 2,35,368 | 1,35,834 | 48,733 | 14,263 | 7,316 | 2,045 | | | | | | |
| 2013-14 | 472 | 1,34,019 | 1,27,328 (5.0) | 15,139 | 34,769 | 44,925 | 19,909 | 7,105 | 2,677 | 1,472 | | | | | |
| 2014-15 | 326 | 87,601 | 87,253 (0.4) | 98 | 14,822 | 34,589 | 25,765 | 9,535 | 1,246 | 162 | 1,036 | | | | |
| 2015-16 | 346 | 95,371 | 91,781 (3.8) | | 3,787 | 7,434 | 37,517 | 28,628 | 8,079 | 4,964 | 1,152 | 220 | | | |
| 2016-17 | 541 | 1,82,807 | 1,79,249 (2.0) | | 1,352 | 3,952 | 25,388 | 71,186 | 41,075 | 21,643 | 8,566 | 4,001 | 2,086 | | |
| 2017-18 | 485 | 1,72,831 | 1,68,239 (2.6) | | | 620 | 15,184 | 12,445 | 63,001 | 41,436 | 22,767 | 10,202 | 2,342 | 242 | |
| 2018-19 | 409 | 1,76,581 | 1,59,189 (9.8) | | | | 569 | 6,862 | 11,000 | 59,973 | 47,080 | 21,248 | 9,759 | 2,663 | 35 |
| 2019-20 | 320 | 2,00,038 | 1,75,830 (12.1) | | | | | | 4,049 | 14,524 | 53,978 | 58,556 | 28,116 | 14,114 | 2,493 |
| 2020-21 | 220 | 75,558 | 75,558 (0.0) | | | | | | | 2,491 | 3,709 | 29,013 | 26,166 | 9,711 | 4,468 |
| 2021-22 | 403 | 1,43,314 | | | | | | | | | 3,610 | 10,258 | 59,897 | 44,282 | 25,267 |
| **कुल और** | | | | **2,50,605** | **1,90,564** | **1,40,253** | **1,38,595** | **1,43,077** | **1,33,172** | **1,46,665** | **1,41,898** | **1,33,498** | **1,28,366** | **71,012** | **32,263** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | | | | | **-24.0** | **-26.4** | **-1.2** | **3.2** | **-6.9** | **10.1** | **-3.3** | **-5.9** | **-3.8** | **#** | |

&: कॉलम के योग किसी विशेष वर्ष में परिकल्पित कैपेक्स को दर्शाते हैं, जिसमें विभिन्न वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अनुमान पूर्व-पूर्व है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए से भिन्न हैं।

#: 2022-23 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2022-23 में स्वीकृत होने वाले प्रस्ताव से कैपेक्स पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

^: ब्रैकेट में आंकड़े संशोधन/रद्दीकरण का प्रतिशत हैं।

### सारणी ए2: कैपेक्स परियोजनाओं की चरणबद्धता * ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी ** के माध्यम से वित्त पोषित**

| में अनुबंधित ऋण ↓ | जारी किए गए एलआरएन की संख्या | कुल अनुबंधित ऋण (₹ करोड़) | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2022-23 से आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2012-13 तक | | | 53,465 | 22,667 | 6,400 | 1,333 | | | | | | | | |
| 2013-14 | 563 | 80,736 | | 56,197 | 20,976 | 3,563 | | | | | | | | |
| 2014-15 | 478 | 57,327 | | | 36,791 | 16,806 | 3,151 | 575 | 2 | 2 | | | | |
| 2015-16 | 314 | 38,885 | | | | 28,998 | 7,311 | 2,572 | 4 | | | | | |
| 2016-17 | 346 | 22,154 | | | | | 14,953 | 6,005 | 1,192 | 2 | 2 | | | |
| 2017-18 | 419 | 37,896 | | | | | | 17,822 | 13,054 | 6,484 | 529 | 7 | | |
| 2018-19 | 515 | 72,490 | | | | | | | 46,221 | 17,725 | 1,236 | 5,398 | 1,844 | 66 |
| 2019-20 | 495 | 95,491 | | | | | | | | 65,367 | 17,157 | 11,717 | 965 | 285 |
| 2020-21 | 344 | 40,382 | | | | | | | | | 18,084 | 21,523 | 642 | 133 |
| 2021-22 | 361 | 47,824 | | | | | | | | | | 25,533 | 21,793 | 498 |
| **कुल और** | | | **53,465** | **78,864** | **64,167** | **50,700** | **25,415** | **26,974** | **60,473** | **89,580** | **37,008** | **64,178** | **25,244** | **982** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | | | | **47.5** | **-18.6** | **-21.0** | **-49.9** | **6.1** | **124.2** | **48.1** | **-58.7** | **73.4** | **#** | |

*: वे परियोजनाएँ जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

**: 2016-17 से रुपये में मूल्यवर्गीकृत बांड (आरडीबी) शामिल किए गए हैं।

#: 2022-23 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2022-23 में निकाले जाने वाले प्रस्तावों से कै पेक्स पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

और: अनुमान पूर्व-पूर्व है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है। वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए से भिन्न हैं।

एलआरएन : ऋण पंजीकरण संख्या

## सारणी ए3: इक्विटी इश्यू के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता*

| इक्विटी के दौरान जारी किया गया ↓ | कंपनियों की संख्या | कैपेक्स परिकल्पित (₹ करोड़) | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2022-23 से आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2012-13 तक | | | 988 | 494 | 108 | | | | | | | | | |
| 2013-14 | 21 | 454 | | | 384 | 70 | | | | | | | | |
| 2014-15 | 24 | 1,078 | | | 189 | 557 | 332 | | | | | | | |
| 2015-16 | 40 | 4,511 | | | 11 | 644 | 2,753 | 849 | 183 | 71 | | | | |
| 2016-17 | 29 | 1,159 | | | | 14 | 471 | 368 | 163 | 143 | | | | |
| 2017-18 | 51 | 1,538 | | | | | | 419 | 327 | 787 | 5 | | | |
| 2018-19 | 39 | 609 | | | | | | | 506 | 90 | 13 | | | |
| 2019-20 | 12 | 53 | | | | | | | 2 | 49 | 2 | | | |
| 2020-21 | 12 | 663 | | | | | | | | | 139 | 421 | 84 | 19 |
| 2021-22 | 27 | 3,410 | | | | | | | | | 10 | 757 | 1,304 | 1,339 |
| **कुल** और | | | **988** | **494** | **692** | **1,285** | **3,556** | **1,636** | **1,181** | **1,140** | **169** | **1,178** | **1,388** | **1,358** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | | | | **-50.0** | **40.1** | **85.7** | **176.7** | **-54.0** | **-27.8** | **-3.5** | **-85.2** | **597.0** | **#** | |

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

#: 2022-23 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2022-23 में लागू होने वाले प्रस्तावों से कैपेक्स पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

और: अनुमान पूर्व-पूर्व में केवल परिकल्पित निवेश को शामिल कर रहा है, वे उनसे अलग हैं वास्तव में महसूस/उपयोग किया गया।

## सारणी ए4: बैंकों/वित्तीय संस्थानों/आईपीओ/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता*

| स्वीकृति का वर्ष ↓ | कंपनियों की संख्या बैंक/वित्तीय संस्थान/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी/आईपीओ | परियोजना लागत (₹ करोड़) | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2022-23 से आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2012-13 तक | | | 2,89,821 | 1,58,995 | 55,241 | 15,596 | 7,316 | 2,045 | | | | | | |
| 2013-14 | 1056 | 2,08,518 | 15,139 | 90,966 | 66,285 | 23,542 | 7,105 | 2,677 | 1,472 | | | | | |
| 2014-15 | 828 | 1,45,658 | 98 | 14,822 | 71,569 | 43,128 | 13,018 | 1,821 | 164 | 1,038 | | | | |
| 2015-16 | 700 | 1,35,177 | | 3,787 | 7,445 | 67,159 | 38,692 | 11,500 | 5,151 | 1,223 | 220 | | | |
| 2016-17 | 916 | 2,02,562 | | 1,352 | 3,952 | 25,402 | 86,610 | 47,448 | 22,998 | 8,711 | 4,003 | 2,086 | | |
| 2017-18 | 955 | 2,07,673 | | | 620 | 15,184 | 12,445 | 81,242 | 54,817 | 30,038 | 10,736 | 2,349 | 242 | |
| 2018-19 | 963 | 2,32,288 | | | | 569 | 6,862 | 11,000 | 1,06,700 | 64,895 | 22,497 | 15,157 | 4,507 | 101 |
| 2019-20 | 827 | 2,71,374 | | | | | | 4,049 | 14,526 | 1,19,394 | 75,715 | 39,833 | 15,079 | 2,778 |
| 2020-21 | 576 | 1,16,603 | | | | | | | 2,491 | 3,709 | 47,236 | 48,110 | 10,437 | 4,620 |
| 2021-22 | 791 | 1,94,548 | | | | | | | | 3,610 | 10,268 | 86,187 | 67,379 | 27,104 |
| **कुल** और | | | **3,05,058** | **2,69,922** | **2,05,112** | **1,90,580** | **1,72,048** | **1,61,782** | **2,08,319** | **2,32,618** | **1,70,675** | **1,93,722** | **97,644** | **34,603** |
| **प्रतिशत परिवर्तन** | | | | **-11.5** | **-24.0** | **-7.1** | **-9.7** | **-6.0** | **28.8** | **11.7** | **-26.6** | **13.5** | **#** | |

*: 2016-17 से रुपये में मूल्यवर्गित बांड (आरडीबी) शामिल किए गए हैं।

#: 2022-23 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2022-23 में स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्तावों से कैपेक्स पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान पूर्व-पूर्व में केवल परिकल्पित निवेश को शामिल कर रहा है, वे उनसे अलग हैं जो वास्तव में वसूले /उपयोग किए हैं।

## सारणी ए5: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आकार-वार वितरण: 2012-13 से 2021-22

| अवधि | परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी | ₹ 100 करोड़ से कम | ₹100 करोड़ से ₹500 करोड़ | ₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़ | ₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़ | ₹5000 करोड़ और ऊपर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | परियोजनाओं की संख्या | 245 | 119 | 20 | 23 | 7 | **414** |
| | प्रतिशत शेयर | 4.8 | 14.6 | 7.3 | 26.8 | 46.4 | **100 (1,89,483)** |
| 2013-14 | परियोजनाओं की संख्या | 306 | 115 | 25 | 21 | 5 | **472** |
| | प्रतिशत शेयर | 8.3 | 20.0 | 13.9 | 29.1 | 28.7 | **100 (1,27,328)** |
| 2014-15 | परियोजनाओं की संख्या | 223 | 65 | 18 | 19 | 1 | **326** |
| | प्रतिशत शेयर | 9.0 | 16.6 | 14.6 | 47.8 | 12.0 | **100 (87,253)** |
| 2015-16 | परियोजनाओं की संख्या | 214 | 76 | 34 | 21 | 1 | **346** |
| | प्रतिशत शेयर | 8.6 | 20.9 | 26.0 | 38.5 | 5.9 | **100 (91,781)** |
| 2016-17 | परियोजनाओं की संख्या | 287 | 180 | 29 | 40 | 5 | **541** |
| | प्रतिशत शेयर | 5.8 | 23.3 | 11.9 | 41.7 | 17.4 | **100 (1,79,239)** |
| 2017-18 | परियोजनाओं की संख्या | 263 | 149 | 28 | 42 | 3 | **485** |
| | प्रतिशत शेयर | 5.2 | 21.0 | 10.8 | 43.8 | 19.1 | **100 (1,68,239)** |
| 2018-19 | परियोजनाओं की संख्या | 220 | 110 | 39 | 36 | 4 | **409** |
| | प्रतिशत शेयर | 4.8 | 17.0 | 17.0 | 39.6 | 21.6 | **100 (1,59,189)** |
| 2019-20 | परियोजनाओं की संख्या | 150 | 84 | 45 | 36 | 5 | **320** |
| | प्रतिशत शेयर | 3.3 | 11.9 | 18.6 | 37.4 | 28.8 | **100 (1,75,830)** |
| 2020-21 | परियोजनाओं की संख्या | 128 | 52 | 15 | 24 | 1 | **220** |
| | प्रतिशत शेयर | 5.5 | 16.8 | 14.2 | 53.5 | 10.0 | **100 (75,558)** |
| 2021-22 | परियोजनाओं की संख्या | 202 | 126 | 37 | 36 | 2 | **403** |
| | प्रतिशत शेयर | 5.6 | 19.9 | 19.8 | 46.8 | 7.8 | **100 (1,43,314)** |

**टिप्पणी:** i. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत ₹ करोड़ में हैं।

ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सा है। राउंडिंग के कारण प्रतिशत कुल 100 नहीं हो सकते हैं।

## सारणी ए6: 2012-13 से 2021-22 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का प्रयोजन-वार वितरण

| अवधि | परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी | नया | विस्तार और आधुनिकीकरण | विविधता | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | परियोजनाओं की संख्या | 303 | 107 | – | 4 | **414** |
| | प्रतिशत शेयर | 84.2 | 14.7 | – | 1.1 | **100 (1,89,483)** |
| 2013-14 | परियोजनाओं की संख्या | 361 | 95 | 2 | 14 | **472** |
| | प्रतिशत शेयर | 65.2 | 20.1 | – | 14.7 | **100 (1,27,328)** |
| 2014-15 | परियोजनाओं की संख्या | 203 | 92 | 2 | 29 | **326** |
| | प्रतिशत शेयर | 39.4 | 14.7 | 0.2 | 45.7 | **100 (87,253)** |
| 2015-16 | परियोजनाओं की संख्या | 260 | 64 | 3 | 19 | **346** |
| | प्रतिशत शेयर | 73.6 | 14.3 | 0.1 | 12 | **100 (91,781)** |
| 2016-17 | परियोजनाओं की संख्या | 429 | 97 | 4 | 11 | **541** |
| | प्रतिशत शेयर | 78.6 | 9.9 | 0.1 | 11.3 | **100 (1,79,249)** |
| 2017-18 | परियोजनाओं की संख्या | 396 | 80 | 2 | 7 | **485** |
| | प्रतिशत शेयर | 89.0 | 9.5 | 0.1 | 1.5 | **100 (1,68,239)** |
| 2018-19 | परियोजनाओं की संख्या | 309 | 80 | – | 20 | **409** |
| | प्रतिशत शेयर | 76.8 | 19.3 | – | 3.9 | **100 (1,59,189)** |
| 2019-20 | परियोजनाओं की संख्या | 262 | 37 | 1 | 20 | **320** |
| | प्रतिशत शेयर | 79.8 | 13.7 | – | 6.4 | **100 (1,75,830)** |
| 2020-21 | परियोजनाओं की संख्या | 181 | 38 | 1 | – | **220** |
| | प्रतिशत शेयर | 94.1 | 5.9 | – | – | **100 (75,558)** |
| 2021-22 | परियोजनाओं की संख्या | 313 | 89 | 1 | – | **403** |
| | प्रतिशत शेयर | 89.1 | 10.8 | 0.1 | – | **100 (1,43,314)** |

**टिप्पणी:** i. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत ₹ करोड़ में हैं।

ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सा है। राउंडिंग के कारण प्रतिशत कुल 100 नहीं हो सकते।

iii. -: शून्य/ नगण्य।

## सारणी ए7: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योग- वार वितरण: 2012-13 से 2021-22

| उद्योग | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर |
| आधारभूत संरचना | 82 | 47.9 | 87 | 39.8 | 74 | 48.8 | 108 | 72.0 | 204 | 62.6 | 150 | 51.8 | 122 | 60.4 | 99 | 61.5 | 63 | 74.3 | 96 | 56.7 |
| i) शक्ति | 71 | 39.4 | 70 | 35.1 | 65 | 42.2 | 92 | 57.1 | 170 | 45.4 | 117 | 36.5 | 78 | 26.8 | 47 | 32.9 | 35 | 49.3 | 59 | 29.5 |
| ii) दूरसंचार | 2 | 5.6 | 1 | – | 1 | 4.9 | 1 | 0.3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे | 1 | 1.9 | 1 | 0.8 | – | – | 3 | 2.4 | 8 | 5.7 | 6 | 3.1 | 4 | 14.2 | 4 | 8.4 | 1 | 0.1 | 2 | 5.8 |
| iv) भंडारण और जल प्रबंधन | – | – | 5 | 1.1 | 2 | 0.6 | 4 | 4.2 | 6 | 3.7 | 2 | 0.4 | 13 | 5.7 | 4 | 0.4 | 5 | 1.2 | 2 | 0.2 |
| v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क | 8 | 0.9 | 8 | 1.5 | 3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 2 | 0.4 | 9 | 1.6 | 11 | 3.2 | 8 | 1.3 | 5 | 2.2 | 3 | 1.1 |
| vi) सड़कें और पुल | – | – | 2 | 1.2 | 3 | 0.3 | 7 | 7.6 | 17 | 7.3 | 16 | 10.1 | 16 | 10.4 | 36 | 18.5 | 17 | 21.5 | 30 | 20.1 |
| निर्माण | 20 | 2.8 | 27 | 2.1 | 29 | 4.0 | 26 | 1.8 | 60 | 12.0 | 39 | 5.3 | 26 | 2.3 | 44 | 11.4 | 27 | 4.8 | 23 | 7.3 |
| कपड़ा | 31 | 1.9 | 58 | 10.3 | 50 | 4.1 | 49 | 4.8 | 57 | 4.1 | 54 | 3.7 | 27 | 3.4 | 11 | 0.5 | 15 | 1.8 | 56 | 4.5 |
| विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स | 10 | 1.9 | 9 | 2.0 | 7 | 0.2 | 2 | 0.2 | 9 | 0.2 | 6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 4 | – | 1 | 0.1 | 5 | 4.0 |
| धातु और धातु उत्पाद | 51 | 28.9 | 44 | 17.0 | 17 | 17.4 | 14 | 1.5 | 23 | 4.9 | 21 | 9.7 | 16 | 3.0 | 14 | 0.8 | 6 | 0.8 | 27 | 3.9 |
| रसायन और उर्वरक | 19 | 1.1 | 15 | 1.0 | 7 | 2.6 | 11 | 1.6 | 10 | 2.1 | 23 | 11.4 | 19 | 2.9 | 12 | 1.3 | 9 | 1.6 | 20 | 3.4 |
| सीमेंट | 11 | 3.9 | 12 | 7.1 | 7 | 3.8 | 5 | 1.9 | 5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 10 | 5.1 | 2 | 0.1 | 5 | 1.3 | 3 | 3.2 |
| परिवहन सेवाएं | 16 | 1.7 | 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 10 | 1.2 | 12 | 0.4 | 16 | 4.1 | 5 | 0.2 | 14 | 1.4 | 1 | 0.1 | 19 | 2.5 |
| अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं | 17 | 1.4 | 10 | 0.7 | 2 | 0.1 | 1 | – | 22 | 1.1 | 18 | 1.8 | 15 | 2.6 | 12 | 0.7 | 7 | 0.3 | 19 | 2.3 |
| खाद्य उत्पाद | 36 | 0.9 | 43 | 1.8 | 34 | 2.9 | 26 | 1.8 | 38 | 0.9 | 47 | 2.8 | 28 | 1.4 | 32 | 1.9 | 20 | 1.5 | 25 | 1.7 |
| दवाइयों | 10 | 0.4 | 19 | 1.3 | 9 | 1.5 | 11 | 0.3 | 12 | 1.1 | 15 | 0.6 | 23 | 1.6 | 9 | 0.6 | 7 | 0.5 | 20 | 1.3 |
| गैर-विद्युत मशीनरी का निर्माण | 9 | 0.7 | 6 | 1.2 | – | – | – | – | 4 | 0.2 | 2 | – | 20 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 7 | 1.3 |
| मुद्रण और प्रकाशन | 1 | – | 2 | 4.2 | 1 | – | 1 | – | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | – | – | 1 | 0.6 | – | – | 1 | 1.1 |
| कांच और मिट्टी के बर्तन | 3 | – | 11 | 0.3 | 19 | 0.7 | 8 | 0.5 | 19 | 0.6 | 20 | 0.8 | 2 | – | – | – | 12 | 0.6 | 9 | 1.1 |
| कोक और पेट्रोलियम उत्पाद | – | – | 1 | 0.5 | 1 | 3.4 | 2 | 2.0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.4 | – | – | 3 | 8.0 | – | – | 7 | 1.0 |
| अन्य* | 98 | 6.2 | 113 | 10.2 | 64 | 9.8 | 72 | 10.3 | 61 | 7.0 | 69 | 6.9 | 95 | 13.2 | 60 | 10.9 | 44 | 12.2 | 66 | 4.7 |
| **कुल** | **414** | **100** | **472** | **100** | **326** | **100** | **346** | **100** | **541** | **100** | **485** | **100** | **409** | **100** | **320** | **100** | **220** | **100** | **403** | **100** |
| **परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़ में)** | **1,89,483** | | **1,27,328** | | **87,253** | | **91,781** | | **1,79,249** | | **1,68,239** | | **1,59,189** | | **1,75,830** | | **75,558** | | **1,43,314** | |

*: होटल और रेस्तरां, रबर और प्लास्टिक उत्पाद, आईटी सॉफ्टवेयर, चीनी और संबद्ध उत्पाद, परिवहन उपकरण, कागज और कागज उत्पाद, कृषि और संबंधित गतिविधियां, खनन और उत्खनन, मनोरंजन, सेवाओं का व्यापार, अन्य विनिर्माण, अन्य सेवाएं जैसे उद्योग शामिल हैं।

**टिप्पणी:** i. प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। राउंडिंग के कारण प्रतिशत कुल 100 नहीं हो सकते हैं।

ii. -: शून्य/नगण्य।

## सारणी ए8: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण: 2012-13 से 2021-22

| उद्योग | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर | परियोजनाओं की संख्या | प्रतिशत शेयर |
| राजस्थान | 41 | 5.3 | 24 | 1.4 | 29 | 11.1 | 10 | 0.9 | 23 | 2.8 | 33 | 6.3 | 21 | 7.7 | 23 | 3.8 | 21 | 17.1 | 33 | 13.3 |
| उत्तर प्रदेश | 26 | 4.4 | 21 | 1.1 | 20 | 5.4 | 15 | 2.5 | 22 | 3.7 | 30 | 2.4 | 28 | 4.8 | 24 | 5.6 | 30 | 13.7 | 33 | 12.9 |
| गुजरात | 58 | 5.6 | 66 | 14.5 | 71 | 9.5 | 61 | 15.1 | 102 | 23.0 | 71 | 8.0 | 56 | 11.1 | 47 | 15.1 | 54 | 17.1 | 83 | 11.9 |
| महाराष्ट्र | 67 | 10.7 | 76 | 19.7 | 38 | 14.8 | 36 | 9.4 | 57 | 8.8 | 65 | 23.3 | 34 | 11.5 | 41 | 6.9 | 13 | 8.5 | 44 | 9.5 |
| तमिलनाडु | 22 | 1.8 | 33 | 5.4 | 27 | 2.9 | 26 | 9.3 | 23 | 4.4 | 28 | 6.6 | 32 | 12.8 | 28 | 8.3 | 7 | 0.7 | 40 | 8.7 |
| कर्णाटक | 20 | 1.6 | 39 | 6.2 | 27 | 5.4 | 21 | 6.2 | 52 | 6.8 | 64 | 9.6 | 34 | 5.7 | 33 | 17.2 | 11 | 6.1 | 24 | 6.8 |
| केरल | 3 | 0.3 | 3 | – | 4 | 0.2 | 4 | 0.1 | 6 | 2.7 | 3 | 0.1 | 6 | 0.9 | 3 | 1.0 | - | - | 5 | 4.2 |
| Madhya Pradesh | 13 | 3.9 | 30 | 6.1 | 14 | 3.9 | 21 | 7.0 | 18 | 7.5 | 10 | 0.7 | 12 | 1.6 | 10 | 1.2 | 19 | 2.8 | 18 | 4.1 |
| बिहार | 7 | 0.1 | 6 | 0.2 | 4 | 0.1 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.1 | 6 | 0.4 | 6 | 3.4 | 1 | – | 5 | 3.3 |
| तेलंगाना | - | - | - | - | - | - | 10 | 3.8 | 51 | 5.5 | 17 | 1.9 | 26 | 9.1 | 12 | 4.0 | 9 | 1.9 | 15 | 3.0 |
| Goa | 2 | 0.2 | - | - | - | - | 1 | – | 3 | 0.6 | 2 | 1.9 | 3 | 1.8 | 2 | 0.1 | - | - | 3 | 2.9 |
| पश्चिम बंगाल | 13 | 1.0 | 12 | 1.2 | 9 | 1.3 | 14 | 3.1 | 18 | 1.7 | 14 | 1.8 | 13 | 1.1 | 7 | 0.9 | 3 | 0.4 | 11 | 2.6 |
| आंध्र प्रदेश | 35 | 5.7 | 37 | 4.0 | 24 | 8.1 | 33 | 12.3 | 47 | 8.0 | 22 | 9.9 | 29 | 11.1 | 12 | 4.0 | 7 | 15.0 | 12 | 2.3 |
| ओडिशा | 10 | 26.8 | 10 | 11.7 | 5 | 15.9 | 6 | 3.1 | 6 | 3.1 | 5 | 3.0 | 9 | 1.4 | 6 | 1.9 | 2 | 0.1 | 9 | 2.1 |
| पंजाब | 12 | 10.9 | 28 | 1.5 | 6 | 0.3 | 11 | 1.7 | 29 | 2.1 | 31 | 2.2 | 15 | 1.9 | 9 | 0.8 | 4 | 0.7 | 15 | 2.1 |
| हरियाणा | 18 | 1.2 | 15 | 1.1 | 11 | 1.9 | 16 | 3.6 | 13 | 1.6 | 21 | 0.5 | 18 | 1.7 | 20 | 3.4 | 15 | 7.8 | 14 | 2.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 5 | 0.3 | 3 | 1.8 | 3 | 0.1 | 8 | 1.4 | 1 | – | 8 | 2.3 | 7 | 0.3 | 6 | 0.1 | 4 | 0.2 | 7 | 1.2 |
| झारखंड | 8 | 1.2 | 4 | 0.3 | 2 | 0.7 | 5 | 0.3 | 1 | – | 3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 4 | 9.4 | 1 | 0.2 | 6 | 0.8 |
| दिल्ली | 4 | 0.6 | 5 | 0.4 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 6 | 1.2 | 8 | 1.3 | 3 | 0.6 | 2 | 0.1 | 3 | 0.6 |
| छत्तीसगढ़ | 9 | 4.1 | 16 | 10.7 | 8 | 7.4 | 8 | 4.6 | 15 | 4.0 | 7 | 4.8 | 6 | 0.9 | 6 | 0.2 | 3 | 1.2 | 4 | 0.6 |
| मल्टी-स्टेट # | 15 | 7.7 | 21 | 6.9 | 10 | 9.5 | 13 | 13.5 | 17 | 11.8 | 16 | 7.5 | 15 | 9.8 | 8 | 11.7 | 2 | 1.4 | 7 | 4.0 |
| अन्य* | 26 | 6.8 | 23 | 5.7 | 12 | 1.3 | 20 | 1.6 | 28 | 1.3 | 26 | 5.6 | 29 | 3.0 | 10 | 0.5 | 12 | 5.2 | 12 | 0.9 |
| **कुल** | **414** | **100** | **472** | **100** | **326** | **100** | **346** | **100** | **541** | **100** | **485** | **100** | **409** | **100** | **320** | **100** | **220** | **100** | **403** | **100** |
| **परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़ में)** | **1,89,483** | | **1,27,328** | | **87,253** | | **91,781** | | **1,79,249** | | **1,68,239** | | **1,59,189** | | **1,75,830** | | **75,558** | | **1,43,314** | |

#: कई राज्यों में परियोजनाओं का संकलन करें।

*: शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करें।

**टिप्पणी:** i. प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। राउंडिंग के कारण प्रतिशत कुल 100 नहीं हो सकते हैं।

ii. -: शून्य/नगण्य।